अतः प्रधान मंत्री से प्रार्थना है कि या तो नया पूर्ण बिल शीघ्र पेश कराकर पास करायें या संशोधनों, के साथ इसी लैंड एक्वीजशन संशोधक 1982 को पास कराने की कृपा करें ताकि किसानों के साथ हो रहा अन्याय रुक जाये।

(viii) *Admission of SC and ST Students in Delhi University.*

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : मान्यवर मैं सरकार का ध्यान अत्यंत ही लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आज भी अनुसूचित जाति एवं जनजाति के सदस्य किस तरह उपेक्षित एवं घृणित नज़र देखे जाते हैं उसका ज्वलंत उदाहरण दिल्ली विश्वविद्यालय है। दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के लिए अन्डर ग्रेजुएट में साढ़े 22 प्रतिशत स्थान सुरक्षित हैं। पांच हजार स्थान इन समुदायों के लिए सुरक्षित हैं, लेकिन सिर्फ 1500 छात्रों ने ही नामांकन हेतु आवेदन दिया है और उन लोगों के आवेदन पत्र पर भी विचार नहीं किया जा रहा है। गरीब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र दिल्ली में दर-दर ठोकर खा रहे हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के अधीन संचालित प्रायः सभी महा विद्यालयों ने इन समुदायों के छात्रों को प्रवेश देने से इन्कार कर दिया है। लगता है दिल्ली विश्वविद्यालय में कोई नियम कानून ही नहीं है। जब दिल्ली विश्वविद्यालय की यह स्थिति है तो देश के अन्य भागों में क्या धांधली होती होगी इसका अन्दाजा आसानी से लगाया जा सकता है। दिल्ली विश्वविद्यालय के उप-कुलपति ने इन समुदायों के छात्रों के नामांकन हेतु 23 जुलाई, 1983 को संबंधित प्राचार्यों को लिखा है, लेकिन उसके पालन की बात तो दूर रही, दिल्ली के एक कालेज के प्राचार्य ने अनुसूचित जाति के छात्रों को भद्दी-भद्दी गालियां दीं तथा पुलिस को बुलाकर उन्हें बाहर करवा दिया।

यह गम्भीर बात है। सरकार इसे गंभीरता से ले। जातिगत द्वेष रखने वाले प्राचार्य के खिलाफ़ कार्यवाही करे तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रों के नामांकन की व्यवस्था करें।

(*ix*) *Law and order situation in Delhi.*

SHRI ATAL BIHARI VAJPAYEE (New Delhi) : The gruesome murder of former Ambassador Khilnani and his wife in a posh locality like Maharani Bagh on July 27, has sent a shock wave among the people of Delhi. Failure to apprehend the culprits responsible for the brutal crime, and even to find a firm clue till now, is causing grave concern and anxiety to the citizens of Delhi for the security of their life and property. Of late, there have been several other cases of crimes like murder, robbery, rape etc. in which the law and order authorities have failed miserably to bring the culprits to book. After the recent changes in the Police set up in Delhi, people were assured of an improvement in the law and order situation. But recent spurt in major crimes has shaken people's faith in the ability of the Administration to ensure the security of their life, property and honour.

I demand that the Home Minister be directed to make a statement in the House on the deteriorating law and order situation in Delhi.

I also demand that the Home Minister and Lt. Governor of Delhi should regularly convene meetings of the Members of Parliament from Delhi to review the position in respect of law and order.

14.56 hrs.

NATIONAL OILSEEDS AND VEGETABLE OILS DEVELOPMENT BOARD BILL.—*contd.* AND VEGETABLE OILS CEES BILL—*contd*.